

'मेरे काम पर सवाल न हो, कोशिश यही'

गवर्नर की भूमिका पर उठ रहे सवालों पर राम नाईक ने दिया जवाब, बोले-सरकार को लगता है कि मेरा काम बीजेपी को सूट कर रहा तो वह सुधार करे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सख्त कदम की जरूरत

Premshanker.mishra@
timesgroup.com

■ **लखनऊ:** यूपी के गवर्नर राम नाईक 22 जुलाई को राजभवन में अपने दो साल पूरे करेंगे। दशकों बाद ऐसा है जब यूपी में सरकार और सियासत के समानांतर सुखियां राजभवन ने बटोरी हैं। हालांकि राम नाईक अपना हर कदम संविधान के दायरे में मानते हैं। गवर्नरों

की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट तक में उठ रहे सवालों पर उनका

22
जुलाई को
राजभवन में दो
साल पूरे करेंगे
राम नाईक

जवाब यही है कि 'मेरी कोशिश यही है कि जो दूसरों के बारे में कहा गया, वह काम मुझसे न हो।' सोमवार को एनबीटी से बातचीत में उन्होंने दो साल के कामकाज और उससे जुड़े सवालों के जवाब दिए- राजभवन से राजनीति में लौटने का दौर फिर आ गया है। शीला दीक्षित नजीर हैं। आप का क्या मत है?

मैं सक्रिय हूँ, राजनीति में नहीं हूँ। आठ बार मुंबई में चुनाव जीतने व दो बार हारने के बाद मैंने 2013 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। जिस कैडिडेट को जिताने की मुझ पर जिम्मेदारी थी, वह रेकार्ड वोट से जीता। समाजसेवा के कई माध्यम हैं। सेहत जब तक साथ देगी मैं काम करता रहूंगा। हम तो बैद्री की तरह हैं। जब तक गाड़ी चलती रहेगी, बैद्री भी चार्ज होती रहेगी।

आरोप तो यही है कि आप की कार्रवाइयां बीजेपी के एजेंडे को सूट करती हैं?

सरकार को ऐसा लगता है तो सुधार के लिए कदम उठाए। मैं किसी विषय पर नुक्ता चीनी नहीं करता हूँ। मैं मेट्रो की रेलिंग से लेकर मथुरा के जवाहरबाग तक अपने सुझाव सरकार को देते रहता हूँ। संविधान की लक्ष्मण रेखा का हमेशा ध्यान रखा है।

आपकी सक्रियता को 'अति सक्रियता' के तौर पर देखा जाता है?

यह देखने वाले का चश्मा है कि वह क्या, कैसे देखता है। इसका कारण यह भी है कि मौजूदा पीढ़ी को शायद इसकी आदत न हो। मुझसे पहले के तीन गवर्नर ब्यूरोक्रेट थे। मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ। जनता की अपेक्षाएं समझता हूँ।

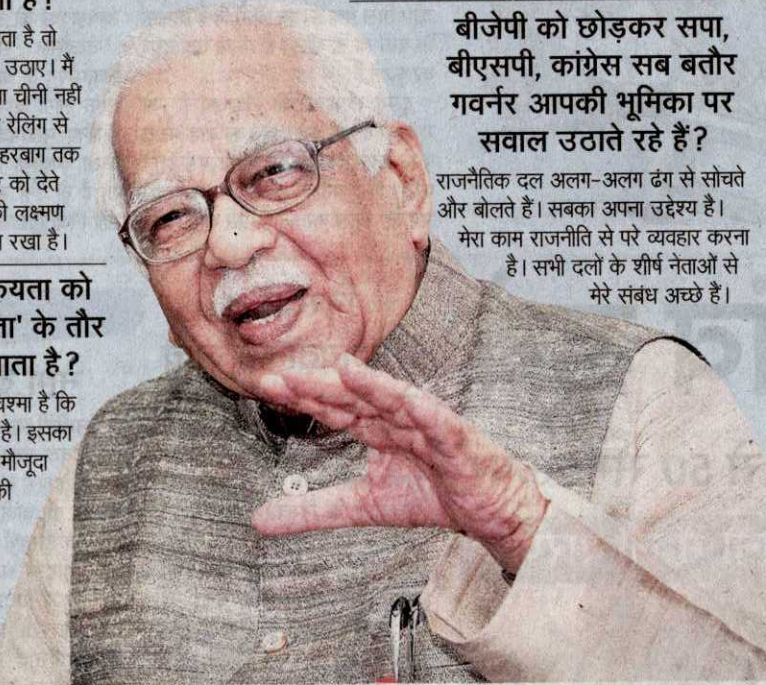
आगे का एजेंडा क्या होगा? हाल ही में मेरा सम्स्मरण 'चरैवेति, चरैवेति' मराठी में प्रकाशित हुआ, जिसका अर्थ है 'चलते रहो'। यही मेरा एजेंडा भी है।

अपने दो वर्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं?

धारणा थी कि गवर्नर का पद रिटायरमेंट व आराम का है। मैं उस सोच को बदलने में सफल रहा हूँ। उपलब्धियों का आकलन जनता को करना है। 1978 में पहली बार विधायक बनने से राजभवन तक मैं अपना रिपोर्ट कार्ड देता रहा हूँ, इस बार भी दूंगा।

बीजेपी को छोड़कर सपा, बीएसपी, कांग्रेस सब बतौर गवर्नर आपकी भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं?

राजनैतिक दल अलग-अलग ढंग से सोचते और बोलते हैं। सबका अपना उद्देश्य है। मेरा काम राजनीति से परे व्यवहार करना है। सभी दलों के शीर्ष नेताओं से मेरे संबंध अच्छे हैं।



संस्मरण के हिंदी, उर्दू अनुवाद भी अगले महीने आएंगे। यूपी को पहले से अधिक समझ सका हूँ। यूपी की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू ने कहा था कि गवर्नर सोने

के पिंजरे में चिड़िया की तरह है। मैं तो इसे नहीं मानता पर मेरी पत्नी जरूर कहती हैं कि वह राजभवन में पिंजरे की चिड़िया की तरह हैं।

कैराना-दादरी रिपोर्ट पर आपका जोर रहा?

कैराना हो या दादरी, कानून व्यवस्था के लिहाज से ये अहम मुद्दे हैं। कैराना में सांसद ने एक बात रखी और एक वृष्टि से सीएम ने उसका संज्ञान लिया। हालांकि इसमें सरकारी जांच दल के बजाय एक मंत्री ने संतों की टीम भेज दी। अगर सीएम जांच कराते तो उसका ऑर्डर जारी करते। जांच टीम ने वहां के बीजेपी सांसद व सपा विधायक को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। मैंने संतों से पूछा तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बात तक नहीं की थी। यह तो बिना सुनवाई फांसी पर चढ़ाना हुआ। दादरी पर तत्कालीन चर्चा क्या थी और आज गोमांस मिलने की बात है। यह कानून व्यवस्था का हाल बताता है। मेरी भूमिका दोषारोपण की नहीं, सलाह देने की है।

उत्तराखंड से अरुणाचल तक गवर्नरों की भूमिका पर सवाल हैं? सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में मुद्दा उठ रहा है?

यह गवर्नर के दायरे की बाहर की चर्चा है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। यह जरूर है कि जो भी कुछ कहा गया ऐसा व्यवहार मेरी ओर से न हो इसकी कोशिश मैं हमेशा करता रहूंगा।

सत्तारूढ़ दल आरोप लगाता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर सरकार से रिपोर्ट मांगते हैं?

यह बात सीएम कहते तो अलग बात होती। राजनैतिक हमलों का उत्तर देना मैं उचित नहीं मानता। संविधान मेरी आंखें हैं। उसके तहत गवर्नर का काम है सलाह देना और जहां जरूरत है सरकार को बताना।

इन दो वर्षों की प्रदेश की सबसे बड़ी घटना?

लॉ एंड ऑर्डर वह पहलू है, जिसमें सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है। मथुरा की घटना को बहुत बड़ा मानता हूँ। कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने गई पुलिस फोर्स पर हमला गंभीर विषय है। प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जा लॉ एंड ऑर्डर को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। इसलिए मैंने सीएम को इस पर श्वेत पत्र लाने का सुझाव दिया।